भाज

भाज ३.०० तीन रुपये मात्र

गौरवशाली परम्परा

गौरवशाली परंपरा का १०७ वर्ष

मां विन्ध्यवासिनी दरबार

विन्ध्य पर्वतकी अंचलमें विद्यमान



वाराणसी, बुधवार १४ अक्तूबर, २०२६ सौर २८, आश्विन शुक्ल ४, २०८३ वि.। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज (रीवा संस्करण), कानपुर (झांसी संस्करण), लखनऊ, आगरा, बरेली, हल्द्वानी,पटना (कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | * काशी संस्करण पृष्ठ १२, मूल्य ३.०० रुपये

चुनाव आयुक्तोंको कानूनी कारवाई से मिली छूटपर अदालत सख्त

केन्द्र और चुनाव आयोगसे मांगा जवाब

नयी दिल्ली (आससे)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के लिए कानूनी कारवाई से मिली व्यापक छूट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत के इस कदम से चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी सुरक्षा और उनकी जवाबदेही से जुड़े सवाल फिर चर्चा में आ गये हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की व्यापक छूट संवैधानिक पदों पर



बैठे अधिकारियों को सामान्य कानूनी प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई (शेष पृष्ठ ९ पर)

सीईसीके खिलाफ प्रदर्शन मामलेकी सुनवाई १५ अक्तूबर तक टली

नयी दिल्ली (आससे)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी है। पीठ की सदस्य न्यायमूर्ति वी. मोहना की तबीयत खराब होने और केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने के कारण यह फैसला लिया गया। न्यायालय ने केंद्र को अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, इंटरनेट बंद करने और (शेष पृष्ठ ९ पर)

दो हजारसे अधिकके यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क दिवाली तक टला

नयी दिल्ली (आससे)। दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने का फैसला दिवाली तक टाल दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए चुनिंदा दुकानदारों से जुड़े यूपीआई लेनदेन पर नए शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था। व्यापारी संगठनों ने त्योहारों के बाद तक इस फैसले को टालने की मांग की थी। दुर्गा पूजा और दिवाली के दौरान खरीदारी बढ़ने के साथ यूपीआई भुगतान का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। ऐसे में कारोबारियों को आशंका थी कि त्योहारों के बीच नया शुल्क लागू होने से उन्हें परेशानी हो सकती है। एनपीसीआई के फैसले से कारोबारियों को फिलहाल राहत मिली है। मालूम हो कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी (पीटूएम) यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, तीन हजार रुपये के भुगतान पर व्यापारी को 12 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि, यह शुल्क सभी यूपीआई भुगतानों पर लागू नहीं होगा। इसे लागू करने की समयसीमा दिवाली तक टाल दी गई है।



लोकतंत्रकी रक्षाके लिए मिलकर लड़ेंगे-राहुल

'वोट चोरी' के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान, इंडिया गठबंधनके नेताओंने सरकार और निर्वाचन आयोगपर साधा निशाना

नयी दिल्ली (आससे)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं और विपक्षी सांसदों के साथ चाय पार्टी के बाद कहा कि विपक्ष का मिशन एक है। सभी मिलकर लड़ेंगे और लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने 'वोट चोरी' के खिलाफ आंदोलन जारी रखने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प जताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को चाय पर आमंत्रित किया था। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र की रक्षा के इस जनांदोलन में हम सब एक साथ हैं और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी



कहा कि चाय के बाद सभी नेता मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। राहुल के आवास '5 सुनहरी बाग रोड' पर हुई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, माकपा महासचिव एम. ए. बेबी, भाकपा महासचिव डी. राजा, समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और आनंद भदौरिया तथा तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ संयुक्त विरोध-प्रदर्शनों और आगे की रणनीति पर (शेष पृष्ठ ९ पर)

केंद्रीय मंत्री एल मुरुगनने अपने पद-राज्यसभा सदस्यतासे दिया इस्तीफा



नयी दिल्ली (आससे)। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता, दोनों से इस्तीफा दे दिया है। एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं। अपने पत्र में एल. मुरुगन ने लिखा, %तमिलनाडु की आपकी हालिया यात्रा ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। हर जगह मैंने देखा कि लोगों ने कितने प्यार से आपका स्वागत किया और आपकी मौजूदगी से उनमें कितनी उम्मीद जगी। (शेष पृष्ठ ९ पर)

जंतर-मंतर जा रहे सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका हिरासत में

नयी दिल्ली (आससे)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर हिरासत में ले लिया। दोनों नेताओं को जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। पार्टी के अजिंक्य शिंदे समेत कई अन्य समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा कर यह (शेष पृष्ठ ९ पर)

बैंक भर्ती फर्जीवाड़ा : सीबीआईका छह राज्योंमें छापा, चार गिरफ्तार



नयी दिल्ली (आससे)। सीबीआई ने बैंक भर्ती में पांच साल के पुराने डेटा की जांच के जरिये नौकरी पाने वाले फर्जी अभ्यर्थियों का खुलासा किया है। परीक्षा के दौरान जुटाये गये आंखों के स्कैन (आइरिस) से फर्जीवाड़े के जरिये नौकरी पाने वाले 257 संदिग्ध उम्मीदवार मिले। इनमें 172 अलग-अलग बैंकों में नौकरी कर रहे थे। सीबीआई अब देशभर में अन्य फर्जी अफसरों की तलाश में जुटी है। आईबीपीएस ने इन सभी कार्यरत लोगों के साथ-साथ अन्य संदिग्धों को भी आजीवन के लिए परीक्षा से डिबार कर दिया है। संबंधित बैंकों को उनके सर्विस रूल्स के तहत कड़ी कारवाई करने के (शेष पृष्ठ ९ पर)

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्टसे अंतरिम राहत

नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। राहुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आठ सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

चुनाव आयोग सुधारे अपनी कार्यशैली-अखिलेश

लखनऊ (आससे)। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और नौकरशाही भाजपा के इशारे पर काम कर रही है।



भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रही है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भाजपा सत्ता से हटेगी, तभी यह संकट हटेगा। अखिलेश ने डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर लोहिया पार्क में श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव अयोग का रवैया और कार्य भेदभावपूर्ण है। अब दोबारा से वोट बनाने का अभियान चल रहा है, जिस एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ो रुपए खर्च हुए, प्रचार हुआ और पूरा प्रशासन लगा, अब उसे शून्य कर दिया गया। एसआईआर में किसी का फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मतदाता सूची में लाखों वोट फर्जी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की (शेष पृष्ठ ९ पर)

